शांति के रूप में खाड़ी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-सी. राजा मोहन (निदेशक, इंस्टी. ट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर)

5 मार्च, 2019

"जैसा कि हम देख रहे हैं पश्चिम एशिया भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में जुट गया है। यह राजनीतिक संतुलन को कायम करने के साथ-साथ इस्लामाबाद को प्रेरित करते हुए दिल्ली का सहयोगी बन सकता है।"

विचार यह है कि खाड़ी देशों को दक्षिण एशियाई सुरक्षा में कुछ रुचि हो सकती है लेकिन अधिकांश भारतीय कानों को अजीब-सा लगेगा। जो भूमिका होनी चाहिए है वह यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को कम करने में मदद करने के लिए खाड़ी देशों की महत्वपूर्ण सक्रियता में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान को रिहा करने के लिए दबाव डाला है, जो पिछले हफ्ते पाकिस्तानी वायु सेना के साथ हवाई मुठभेड़ में पकड़े गये थे।

अतीत में, खाड़ी और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई के रूप में कार्य किया गया है। दशकों तक साझा धार्मिक पहचान और क्षेत्रीय मामलों के लिए आम दृष्टिकोण ने पाकिस्तान क्षेत्र में भारत को एक राजनीतिक बढ़त दी।

हालांकि, हाल के वर्षों में, दिल्ली ने इस असंतुलन को ठीक करना शुरू कर दिया है। जितने भी खाड़ी देश हैं, विशेष रूप से सऊदी अरब और यूएई, भारत के साथ मजबूत आर्थिक और सुरक्षा बंधन विकसित करना चाहते हैं, वे पाकिस्तान में राजनीतिक संतुलन और उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय आवास के लिए संभावित सहयोगी बन सकते हैं। यूएई और सऊदी अरब की वित्तीय सहायता पर अपनी अर्थव्यवस्था और निर्भरता के कारण राज्य ने इस तरह के परिणाम के लिए पाकिस्तान को और अधिक उत्तरदायी बना दिया है।

यह कोई नई बात नहीं है। कि भारतीय उपमहाद्वीप और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा हमेशा एक-दुसरे से जुड़ी हुई रही है। इस परस्पर निर्भरता की प्रकृति, निश्चित रूप से, समय और स्थान के साथ बदलती रही है। लेकिन स्वतंत्र भारत ने खाड़ी के साथ इस रणनीतिक घनिष्ठता के महत्व को कम करने की कोशिश की है।

औपनिवेशिक युग में, अविभाजित भारत का खाड़ी देशों पर बड़े पैमाने पर प्रभाव था। उस युग के दौरान, ब्रिटिश शासन अपने सुरक्षा बचाव, वाणिज्य के लिए एक रूपरेखा और कुछ प्रशासनिक सहायता की पेशकश करता रहा है। अविभाजित भारत पर केंद्रित पूर्वी गोलार्द्ध में ग्रेट ब्रिटेन के इंपीरियल डिफेंस सिस्टम की बड़ी वास्तुकला में खाड़ी और मध्य-पूर्व के अन्य स्थान एक महत्वपूर्ण जुड़ाव के रूप में कार्य करते थे।

भारत की सेनाओं को 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में खाड़ी और मध्य-पूर्व में बार-बार होने वाले अभियानों में शामिल होना पड़ता था। इसके अलावा, भारतीय सेनाओं ने दोनों विश्व युद्धों में मध्य-पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने खाड़ी और मध्य पूर्व में किसी भी सुरक्षा भूमिका से खुद को दूर कर लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान भारतीय निकासी द्वारा बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था को भरने के लिए एंग्लो-अमेरिकन प्रयास में शामिल हो गया। यह केन्द्रीय संधि संगठन (CENTO) नामक अल्पकालिक क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन का सदस्य बन गया। इसके क्षेत्रीय सदस्यों में पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की शामिल थे। जहाँ एक तरफ भारत ने मिस्र जैसे राष्ट्रवादी और गुटनिरपेक्ष सरकारों के साथ गठबंधन किया, वहीं पाकिस्तान ने रूढ़िवादी और पश्चिमी शासन की नीति को अपनाया।

जब केंद्रीय संधि संगठन अस्तित्व में नहीं रहा, तब इसने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों के साथ पाकिस्तान के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सहयोग के लिए एक आधार प्रदान किया।1965 और 1971 में भारत के साथ अपने युद्धों के दौरान जॉर्डन, ईरान और तुर्की जैसे कुछ देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। जैसा कि क्षेत्रीय रूढ़िवादियों के संबंध में अरब राष्ट्रवादी शासन लगातार कमजोर होता गया, भारत भी 1970 के दशक में पाकिस्तान के साथ लगातार राजनीतिक आधार खोता गया।

1980 के दशक में मामले और बिगड़ गए क्योंकि भारत अफगानिस्तान के सोवियत कब्जे पर चुप रहा और खाड़ी शासन,

सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया। हालांकि, भारत की ऊर्जा और खाड़ी पर आर्थिक निर्भरता बढ़ी है।

1990 के दशक में पाकिस्तान ने मध्य-पूर्व के भीतर महत्वपूर्ण समर्थन जुटाने पर कार्य किया है जिसमें ओआईसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आंतरिक नीतियों को शामिल किया गया था। बाबरी मस्जिद पर हमला और कश्मीर घाटी में भारत की मुसीबतों ने पाकिस्तान को पर्याप्त रूप से राजनीतिक हमला करने का अवसर प्रदान किया है।

मई, 1998 में भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण और 1999 की गर्मियों में कारगिल संकट ने खाड़ी के साथ दक्षिण एशिया के संबंधों के पुनर्गठन की संभावनाओं को खोल दिया था। 1998-2000 के दौरान जसवंत सिंह और अमेरिकी उपसचिव स्ट्रोब टैलबोट के बीच रणनीतिक वार्ता ने खाड़ी में एक नई और प्रभावशाली भूमिका का निर्माण किया है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने कारगिल युद्ध के दौरान सऊदी अरब का इस्तेमाल किया ताकि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की सेना को वापस बुलाने की भारतीय मांग को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ से भयभीत प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका से सुरक्षा चाहते थे।

वाशिंगटन में प्रभावशाली सऊदी राजदूत बंदार बिन सुल्तान ने 4 जुलाई, 1999 को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ व्हाइट हाउस में शरीफ के लिए एक बैठक आयोजित की। प्रिंस बंदार ने डलेस हवाई अड्डे पर शरीफ की अगवानी की और उन्हें अगली सुबह क्लिंटन के साथ बैठक के लिए तैयार किया। शिमला समझौते के अनुसार, नियंत्रण रेखा को बहाल करने के लिए विवादास्पद समझौते (पाकिस्तान में) पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रिंस बंदार ने सऊदी अरब के साथ मिलकर नवाज शरीफ को वापस घर भेज दिया था।

कारगिल के बाद, एनडीए ने खाड़ी और मध्य-पूर्व के साथ जुड़ाव में एक नया आत्मविश्वास और तीव्रता का निर्माण किया है। जसवंत सिंह वर्ष 2000 के अंत में सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दिल्ली और रियाद दशकों पहले एक-दुसरे से कितने दूर हो गये थे।

यूपीए दशक में सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत एक नई गति प्राप्त हुई है। दो दशक पहले, जसवंत सिंह ने सऊदी, अरब के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पाकिस्तान की अड़चन को उठाने में दिलचस्पी दिखाई थी। आज हाउस ऑफ सऊद उपमहाद्वीप और उससे आगे क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में दिल्ली के लिए एक मूल्यवान साझेदार बन रहा है, जिसका स्वागत है।

GS World टीम...

लुक वेस्ट पॉलिसी

क्या है?

- हाल के समय में भारत ने यूरोप एवं अमेरिका के साथ-साथ पश्चिम एशिया के साथ भी संबंधों को मजबूती देने का प्रयास किया है।
- ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल, फिलिस्तीन जैसे देशों के साथ भारत ने घनिष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया है। भारत की इस नीति को 'लुक वेस्ट पॉलिसी' का नाम दिया जा रहा है।

भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी के सकारात्मक पक्ष

- भारत ने इजरायल के साथ संबंधों को मजबूत बनाया है, किंतु फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को बिगड़ने नहीं दिया है।
- इसी प्रकार भारत ने ईरान के साथ-साथ सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात से भी संबंधों को सशक्त स्थिति में रखा है।
- आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा एवं वैश्विक ध्रुवीकरण के संबंध में भारत एवं पश्चिमी एशियाई देशों की चिंतायें एक जैसी हैं।
- भारत एवं पश्चिम एशियाई देशों के बीच पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट बढ़ता जा रहा है। भारतीय व्यंजन एवं फिल्में पश्चिम एशियाई देशों में पसंद की जा रही हैं।
- बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा पश्चिम एशियाई देशों में निवास कर रहे हैं। ये न सिर्फ भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते हैं, बल्कि भारी मात्रा में रेमिटांस भी भारत में भेजते हैं।

भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी के नकारात्मक पक्ष

- पश्चिम एशियाई देशों के बीच आपसी संघर्ष लगातार जारी है, जो भारत की नीति को अधिक कारगर नहीं होने दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, यमन, सीरिया में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। इसी प्रकार ईरान एवं सऊदी अरब के बीच मतभेद हैं।
- अरब लीग एवं जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद्) जैसे संगठन निष्क्रिय बने हुए हैं।
- भारत की 'लुक ईस्ट नीति' सफल रही है क्योंकि पूर्व में आसियान जैसा मजबूत संगठन है। जबकि पश्चिम एशिया में आसियान जैसा कोई मजबूत संगठन नहीं है। अत: भारत की 'लुक वेस्ट नीति' की सफलता संदेहास्पद है।

भारत के द्वारा उठाये जाने वाले कदम

- भारत को पश्चिम एशियाई देशों के आपसी विवादों में नहीं उलझना चाहिए तथा प्रत्येक देश से द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
- पश्चिम एशियाई देशों के साथ आर्थिक मुद्दों, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट तथा सूचना-प्रौद्योगिकी के मामले में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात व इजरायल जैसे देशों से घनिष्ठता स्थापित करने के प्रयास को भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है।
2. खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब व फिलिस्तीन आदि शामिल हैं।
3. केन्द्रीय संधि संगठन (CENTO) का मुख्यालय अंकारा (तुर्की) में स्थित है। जिसका सदस्य देश भारत नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) उपरोक्त सभी

1. Consider the following statements-

1. India's effort to develop intimacy with Saudi Arabia , UAE and Israel, etc. are considered as part of India' s Look West Policy.
2. UAE, Saudi Arabia and State of Palestine are part of gulf countries.
3. The headquarter of The Central Treaty Organization (CENTO) is located in Ankare (Turkey). India is not its member.

Which of the above statement is/are correct?

(a) Only 2
(b) 1 and 3
(c) 2 and 3
(d) All of the above.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी अपने पड़ोसी व प्रतिद्वन्द्वी देश पाकिस्तान को कैसे नियन्त्रित कर सकेगी? चर्चा कीजिए।

Q. How the Look West Policy of India will control its neighbour and competitive country Pakistan? Discuss.

(250 Words)

नोट : 4 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

Committed To Excellence